



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 8, 1939

No. 340]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSAH 8, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर)।

एफ. संख्या 15/23/2016-डीजीएडी—यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निधारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 4 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/27/2004-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पाटन-रोधी जांच की शुरूआत की थी।

2. और यतः प्रारंभिक जांच परिणाम, अधिसूचना संख्या 14/27/2004-डीजीएडी द्वारा 1 अप्रैल 2006 को जारी किए गए थे और दिनांक 6 जून, 2006 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 54/2006-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे। उसके परिणाम स्वरूप अंतिम जांच परिणाम 3 जनवरी 2007 को जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 42/2007-सीमा-शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से सैकरीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

3. और यतः प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की थी और 6 नवंबर, 2009 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 15/15/2008-डीजीएडी द्वारा शुल्कों में संशोधन किए जाने की सिफारिश की थी। संशोधित शुल्क केन्द्रीय सरकार की सीमा-शुल्क की दिनांक 9 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 136/2009-सीमा-शुल्क द्वारा लगाए गए थे।

4. और यतः तत्पश्चात् प्राधिकारी ने 31 मई, 2010 की अधिसूचना द्वारा उक्त पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा की शुरूआत की थी और दिनांक 7 दिसंबर, 2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/20/2010-डीजीएडी के माध्यम से उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 7/2012-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जनवरी, 2012 द्वारा शुल्कों को आगे 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 12 जनवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया था।

5. और यतः मेसर्ज स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्ज श्री वरदायिनी कैमिकल इंड. प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्ज ए.एस. कैमोप्लार्मा प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा अधिनियम और नियम के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए शुल्क की अवधि को आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सैकरीन के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा की शुरूआत करने की मांग की गई है।

6. इस तथ्य पर संतुष्ट होते हुए कि याचिकादाता ने निर्णायिक समीक्षा जांच शुरू करने की आवश्यकता पर्याप्त प्रमाण युक्त है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 15/23/2016-डीजीएडी द्वारा यह उपयुक्त समझा है कि निर्णायिक समीक्षा जांच शुरू की जाए। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा 12 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

7. मौजूदा निर्णायिक समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आयातों की विगत जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

क. क्रिया-विधि

8. प्राधिकारी द्वारा इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:

- (1) प्राधिकारी ने प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटन-रोधी निर्णायिक जांच समीक्षा शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 15/23/2016-डीजीएडी जारी की थी।
- (2) प्राधिकारी ने दिनांक 10 जनवरी, 2017 की जांच शुरू करने संबंधी इस अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास और उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश से सभी ज्ञात निर्यातिकों, ज्ञात आयातकों और अन्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उत्पादकों को प्रेषित की थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण के उत्तरों के साथ प्रश्नावली के उत्तर और अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करें। निर्यातिकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां चीन के दूतावास को ज्ञात निर्यातिकों/उत्पादकों की सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वह संबद्ध देश के निर्यातिकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (3) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदकों की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृतान्त की प्रति, ज्ञात निर्यातिकों, अन्य घरेलू उत्पादकों और चीन के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी।
- (4) प्राधिकारी ने निर्णायिक जांच समीक्षा शुरू करने की सार्वजनिक सूचना संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों/प्रतिनिधि संगठनों को प्रेषित की थी और उन्हें नियमावली के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था:-

- (क) सुझोऊ फाईन केमिकल्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- (ख) शंघाई फोरचून केमिकल कंपनी लिमिटेड
- (ग) केइफेंग किसनघुआ फाईन केमिकल फैक्टरी
- (घ) टियान्जिन नॉर्थ फूड कंपनी लिमिटेड

(इ) टियान्जिन चांगजी केमिकल कंपनी लिमिटेड
 (च) पीएमसी बेंजिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

(5) तथापि, संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातिक/उत्पादक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने आयातक की प्रश्नावली के साथ जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/प्रतिनिधि संगठनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की थी और उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप से अपने विचारोंसे अवगत कराने की सलाह दी गई थी:-

- (क) ईगल ट्रेडिंग कंपनी
- (ख) कोलगेट पामालिव इंडिया लिमिटेड
- (ग) जनरल इम्पोर्ट कंपनी इंडिया
- (घ) जगमोहनदास एंड सन्स
- (ङ) स्पेसिएलिटी केमिकल्स
- (च) सी. जे. शाह एंड कंपनी
- (छ) ग्रोअर एंड वेल इंडिया लिमिटेड
- (ज) नन्दला बंकटलाल प्राईवेट लिमिटेड
- (झ) नेकटार ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
- (ञ) प्रोक्टर एंड गेंबल हाईजीन एंड हेल्थ
- (ट) सन शाईन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
- (ठ) नीरू मार्किंटिंग प्राईवेट लिमिटेड

(7) तथापि, संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(8) नियम 6 (7) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृतान्त को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया था।

(9) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे सार्वजनिक फाईल में रखा गया था।

(10) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और उनको निर्मित करने और बेचने के आधार पर क्षति रहित कीमत का सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और आकलन किया गया है, ताकि क्षति मार्जिन का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

(11) जांच की अवधि जुलाई, 2015 से सितंबर, 2016 तक (15 महीनों) की है। क्षति की जांच करने की अवधि में वर्ष 2013-14, 2014, 15, 2015-16 और जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।

(12) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी। जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन किया गया था।

(13) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यारे प्रदान करने की व्यवस्था करें। इसलिए प्राधिकारी ने आयात की मात्रा का परिकलन और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए अडीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

(14) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 2 नवंबर, 2017 को एक मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में केवल घरेलू उद्योग और उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। घरेलू उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वह मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।

(15) हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।

(16) इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 67.06 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र और "समान वस्तु"

घरेलू उद्योग के निवेदन

9. विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) विचाराधीन उत्पाद, चीन जनवादी गणराज्य मूल का अथवा वहां से निर्यातित अपने समस्त रूप में "सैकरीन" है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं पर की गई अपनी विगत जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार माना है:-
 "सैकरीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और उसे केन सुगर का कम कैलोरी का प्रतिस्थापन माना जाता है। प्राथमिक रूप से सैकरीन दो प्रकार अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील की होती है। बाजार शब्दाली में घुलनशील सैकरीन को सोडियम सैकरीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैकरीन को अघुलनशील सोडियम सैकरीन कहा जाता है। सोडियम सैकरीन के अलावा, सैकरीन कैल्शियम और जिंक सैकरीन की किस्में हो सकती हैं। सैकरीन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। सोडियम सैकरीन दानेदार रूप में उस स्थिति में जब वह घुल जाता है प्रयोग किया जाता है, पाउडर रूप जो फीसा और स्प्रे ड्राइड होता है का प्रयोग ड्राइ मिश्रण और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा घुलनशील होता है। सैकरीन के अघुलनशील रूप का प्रयोग भेषजों और चिकित्सा अनुप्रयोगों में होता है। सैकरीन का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि में किया जाता है। सैकरीन चीनी से 500 गुना अधिक मिठास वाला होता है। वर्तमान जांच के दायरे के भीतर सैकरीन के सभी प्रकार आते हैं। निर्णयिक समीक्षा जांच होने के कारण, पीयूसी पूर्ववर्ती जांचों के समान रहेगा।

सैकरीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष संख्या 29251100 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात अनेक अन्य टैरिफ उप-शीर्षों के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसकी जांच का उल्लेख नीचे किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाधित नहीं है।

(3) वर्तमान जांच के लागू शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के समान ही रहेगा। इसके अतिरिक्त इस दौरान कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं हुआ है।

(4) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और भारत में आयातित "सैकरीन" भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। नियमावली के अनुसार उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, समान वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं।

निर्णयिकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

10. विचाराधीन उत्पाद के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सैकरीन” है, जिसे मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“सैकरीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और उसे केन सुगर का कम कैलोरी का प्रतिस्थापन माना जाता है। प्राथमिक रूप से सैकरीन दो प्रकार अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील की होती है। बाजार शब्दाली में घुलनशील सैकरीन को सोडियम सैकरीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैकरीन को अघुलनशील सोडियम सैकरीन कहा जाता है। सोडियम सैकरीन के अलावा, सैकरीन कैल्शियम और जिंक सैकरीन की किस्में हो सकती हैं। सैकरीन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। सोडियम सैकरीन दानेदार रूप में उस स्थिति में जब वह घुल जाता है प्रयोग किया जाता है, पाउडर रूप जो फीसा और स्प्रे ड्राइड होता है का प्रयोग ड्राइ मिश्रण और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा घुलनशील होता है। सैकरीन के अघुलनशील रूप का प्रयोग भेषजों और चिकित्सा अनुप्रयोगों में होता है। सैकरीन का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि में किया जाता है। सैकरीन चीनी से 500 गुना अधिक मिठास वाला होता है। वर्तमान जांच के दायरे के भीतर सैकरीन के सभी प्रकार आते हैं। निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, पीयूस पूर्ववर्ती जाँचों के समान रहेगा।

सैकरीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष संख्या 29251100 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात अनेक अन्य टैरिफ उप-शीर्षों के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसकी जांच का उल्लेख नीचे किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाधित नहीं है।

12. चूंकि वर्तमान जांच लागू शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के समान ही रहेगा। इसके अतिरिक्त समीक्षा के दायरे में कोई संशोधन (संक्षेपन सहित) करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

13. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर और दायरे में समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और उसका आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

14. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) आवेदक भारत में समान वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं। आवेदकों का उत्पादन, घरेलू उत्पादन का “एक प्रमुख भाग” बनता है। ब्लू सर्किल आर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है।
- (2) आवेदकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आवेदक जांच किए जा रहे किसी भी निर्यातिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं। साथ ही आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातिक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातिक अथवा प्रयोक्ता से भी संबंधित नहीं हैं।
- (3) वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते कानूनी स्थिति के प्रति विना किसी पूर्वाग्रह के प्राधिकारी को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए आवेदकों के आधार का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिका नियमावली के अंतर्गत आधार की अपेक्षा को पूरा करती है और आवेदक नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषाके भीतर घरेलू उद्योग बनते हैं।

निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

15. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके आधार के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

ड. विविध निवेदन

16. जांच के बहुत विलंबित चरण में मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स ने दिनांक 21.11.2017 के ईमेल द्वारा यह बताया है कि उन्होंने अपने निवेदन भेज दिए हैं लेकिन उन्हें प्राधिकारी से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. मेसर्ज स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्ज श्री वरदायिनी कैमिकल इंड. प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्ज ए.एस. कैमोप्लार्मा प्राईवेट लिमिटेड द्वारा याचिका दायर की गई है। मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकादाता कंपनियों ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। याचिकादाता कंपनियों का उत्पादन, भारतीय उत्पादन का 50% से भी अधिक भाग बनता है। पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग बनते हैं। इस प्रकार पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर आवेदकों को “घरेलू उद्योग” के रूप में माना जा रहा है।

18. प्राधिकारी ने मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स के तर्कों की जांच की है और पाया है कि उसके रिकार्ड के अनुसार मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया और न ही उन्होंने जांच की कार्रवाई में भाग लिया है। प्राधिकारी ने इसके बारे में मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स को सूचित कर दिया है और उन्हें सलाह दी है कि वे अपने दावे के साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त जांच दल द्वारा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई करने का एक अवसर भी प्रदान किया गया था, लेकिन वे उस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने दावे के समर्थन में प्राधिकारी को कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उनके दावे को अस्वीकार कर दिया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

19. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा।
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका नियत उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियतिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को नियति के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन नियति के देश में नहीं होता है, अथवा नियति के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संर्दर्भ में किया जाएगा।

20. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से जात नियतिकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित रूप में औरद तरीके से सूचना प्रदान करें। तथापि, संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/नियतिक ने अपनी प्रश्नावलियों का उत्तर दे कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

21. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) आवेदकों ने श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है।
- (2) वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि जुलाई, 2015 से सितंबर, 2016 तक (15 महीनों) की है। अति की जांच अवधि में वर्ष 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि को शामिल किया गया है।
- (3) जांच अवधि का निर्धारण करने का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है, जब कि पाटन विद्यमान होने के कारण हुई क्षति का दावा किया गया है और उसे सिद्ध किया गया है। घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के

विवादास्पद प्रश्न के लिए तारीख का निर्धारण प्रासंगिक नहीं है। चूंकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और जांच अवधि के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ जांच अवधि के दौरान प्रचलित दशाओं को ही प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक माना जाना चाहिए।

- (4) चीन के उत्पादकों को इस कारण से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माना जाना चाहिए कि चीन में लागत और कीमतें उचित रूप से बाजार प्रतिवलों को प्रतिविवित नहीं करती हैं। अनुबंध-1 के पैरा 8 में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत करने के प्राचल विनिश्चित है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब तक इन शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक चीन की लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता है।
- (5) बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे पर विचार करना, जांच अवधि के दौरान प्रचलित प्राचलों पर आधारित होता है। चूंकि चीन की लागतों और कीमतों को अस्वीकार करने का कारण अनुबंध-1 के पैरा 8 में सूचीबद्ध कारकों के कारण चीन में लागतों और कीमतों का विरूपण है, आवेदकों का निवेदन है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के रूप में चीन के उत्पादकों को माने जाने के निर्णय के लिए यह प्रासंगिक है।
- (6) चूंकि अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से चीन की कंपनियों को दिसंबर, 2016 तक बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से वंचित किया गया है, आवेदकों का निवेदन है कि चीन के उत्पादकों को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माना जाना चाहिए, जब तक कि जांच अवधि में अभिगमन नीति नयाचार में विनिश्चित अवधि को शामिल नहीं कर लिया जाता है।
- (7) नियम 2 (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी घरेलू उत्पादक अथवा उसके किसी निर्यातिक अथवा आयातक के साथ संबंध होने की जांच, केवल जांच अवधि के संदर्भ में की जाए। यदि केवल जांच अवधि, आधार के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल जांच अवधि प्रासंगिक है।
- (8) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले वातावरण में प्रचालन करने वाली कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई कर सकते हैं।
- (9) सामान्य मूल्य का निर्धारण, तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आवेदकों ने भारत में विधिवत् समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का दावा किया है।
- (10) चीन से पाटन मार्जिन न केवल अत्यधिक है, बल्कि पर्याप्त भी है। इस प्रकार इससे भारत में विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक पाटन की मौजूदगी सिद्ध होती है। समस्त वर्तमान जांच अवधि में चीन से आयात की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है।

उ॒.२ निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

22. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

उ॒.३ प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

23. अभिगमन नीति नयाचार में अनुच्छेद 15 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

“गॉट 1994 के अनुच्छेद 6, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटन-रोधी करार”) और एससीएम करार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश में चीन मूल के होने वाले आयातों से संबंधित कार्रवाई पर लागू होते हैं जिनमें निम्नोक्त शामिल हैं:-

- (क) गॉट 1994 के अनुच्छेद 6 और पाटन-रोधी करार के अंतर्गत कीमत में तुलनीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश, जांच अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतें या जांच अधीन उद्योग के लिए लागतें या एक ऐसी कार्य-प्रणाली जो कि घरेलू कीमतों से कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं है या निम्नलिखित नियमों पर आधारित चीन में लागतें का उपयोग करेगा:-

(1) यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं, तो विश्व व्यापार संगठन का आयातक देश कीमत में तुलनीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए चीन की कीमतें अथवा जांच अधीन उद्योग के लिए लागतों को प्रयुक्त करेगा।

(2) विश्व व्यापार संगठन का आयातक देश ऐसी कार्य-प्रणाली प्रयुक्त कर सकता है, जो कि चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित नहीं हैं।

(ख) यदि विश्व व्यापार संगठन के आयातक देश की राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह प्रमाणित हो जाता है कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जायेंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य देश की राष्ट्रीय विधि में अभिगमन की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था का मानदंड निहित हो। किसी भी स्थिति में उप-पैरा (क) (2) के प्रावधान अभिगमन की तारीख से 13 वर्षों के बाद समाप्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि चीन विश्व व्यापार संगठन के आयातक देश की राष्ट्रीय विधि के अनुसरण में यह प्रमाणित कर देता है कि एक विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उक्त उद्योग या क्षेत्र पर बिल्कुल लागू नहीं होंगे।”

24. अनुच्छेद 15 से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त एक उप-पैरा के प्रावधान, चीन के अभिगमन की तारीख से 13 वर्षों के बाद समाप्त हो जायेंगे। इस पैरा के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। चूंकि जांच अवधि के आधार पर घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति के तथ्य की पुष्टि हो चुकी है, जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के दौरान प्रचलित दशाएं ही प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि जून, 2015 से सितंबर, 2016 तक की है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप-पैरा जांच अवधि के दौरान विद्यमान था, प्राधिकारी एक ऐसी कार्य-प्रणाली प्रयुक्त कर सकते हैं, जो कि चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित हो, यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शते हैं कि उक्त उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री करने के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा पाटन-रोधी जांच में चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन जनवादी गणराज्य को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, जब तक कि नियमावली के अनुसार निर्यातिक देश अथवा विशिष्ट निर्यातिकों द्वारा ऐसी पूर्वधारणा का खंडन नहीं कर दिया जाता है।

26. पाटन-रोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातिक पैरा 8 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातिकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या:-

(1) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(2) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, अन्य बट्टेखातों, वस्तु विनियम-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से ही महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(3) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(4) विनियम दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

27. यह नोट किया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा नहीं किया है क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों के लिए उपरोक्त किसी भी मानदंड की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और उनका यह मानना है कि चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचलन नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है।

उ.4 निर्यात कीमत का निर्धारण

28. प्राधिकारी ने चीन में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और साथ ही चीन सरकार को भी प्रश्नावलियां भेजी थीं। तथापि, चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक से प्राधिकारी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्राधिकारी संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ रहे हैं। चीन में सभी उत्पादकों के मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त भारित औसत आयात कीमत के आधार पर किया गया है। कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए रिकार्ड पर उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन प्रभार और वॉट के लिए कीमत में समायोजन किया गया है। तदनुसार, कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

क्रमांक	विवरण	मापन का यूनिट	जांच अवधि
1	आयात की मात्रा	मी.टन	490
2	आयात का मूल्य	लाख रूपए	3,003
3	सीआईएफ मूल्य	रूपए/कि.ग्रा.	613
4	भाड़ा (अमरीकी डालर)/मी.टन	रूपए/कि.ग्रा.	***
5	बीमा (0.5%)	रूपए/कि.ग्रा.	***
6	एफओबी कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***
7	कमीशन	रूपए/कि.ग्रा.	***
8	बैंक प्रभार	रूपए/कि.ग्रा.	***
9	हैंडलिंग प्रभार	रूपए/कि.ग्रा.	***
10	पत्तन व्यय	रूपए/कि.ग्रा.	***
11	वॉट @ 4%	रूपए/कि.ग्रा.	***
12	निबल निर्यात कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***

पाटन मार्जिन

29. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारत में चीन की निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान चीन से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	रूपए/कि.ग्रा.	\$/कि.ग्रा.
संरचित सामान्य मूल्य	***	***
निबल निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	15-25%	15-25 %

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

30. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) भारत में संबंधित उत्पाद की मांग ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है।
- (2) क्षति अवधि में चीन से आयातों में मामूली गिरावट आई है। यह गिरावट संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क के कारण आई है। यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी क्योंकि चीन में उत्पादकों के पास वृहत् मात्रा विद्यमान है और उनके निर्यातोन्मुखी होने के कारण वे संबद्ध वस्तुओं का अधिक अनुपात में निर्यात करने लगेंगे।
- (3) भारत में मांग और उत्पादन की दृष्टि से संबद्ध आयात अत्यधिक हैं। प्रस्तावित जांच अवधि में कुल आयातों में संबद्ध आयातों का बाजार का हिस्सा अत्यधिक है।
- (4) संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। क्षति अवधि में कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है।
- (5) समस्त क्षति अवधि के दौरान विक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार कोई कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव नहीं है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत, विक्रियों की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से नीचे बनी हुई है। इस प्रकार यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर कीमत ह्रास के प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (6) चीन के उत्पादकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों पर विचार करते हुए आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के साथ करने से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप बाजार में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री होने लगेगी।
- (7) उत्पादन और विक्रियों की मात्रा के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, पाटित आयात अभी भी भारतीय बाजार के अत्यधिक भाग को हथियाए हुए हैं। इसके फलस्वरूप विक्रियों, उत्पादन और क्षमता का कम ईष्टतम उपयोग हो रहा है।
- (8) लाभ, नकदी प्रवाह और नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहा था, लेकिन बाजार में पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण लाभप्रदता के रूप में कार्य-निष्पादन कम-ईष्टतम था। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं।
- (9) प्रस्तावित जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक माल-सूचियां बनी रही हैं।
- (10) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग में रोजगार और वैतन में वृद्धि हुई है। ये प्राचल अनेक अन्य प्राचलों पर निर्भर हैं और इनसे घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव का पता नहीं चलता है।
- (11) आधार वर्ष से उत्पादन, विक्रियों, बाजार के हिस्से, लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी लाभ आदि ने सुधार दर्शाया है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देश से पाटित आयातों के विद्यमान होने से संवृद्धि अत्यधिक कम रही है। पाटित आयातों द्वारा अभी भी मांग में अत्यधिक हिस्से को हथियाया जा रहा है।
- (12) विगत निर्णयिक समीक्षा जांच में भी पाटन मार्जिन 19.31% था। जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान पाटन मार्जिन अत्यधिक बना हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि पर्याप्त भी है। पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन तीव्रता से बढ़ जाएगा।

च.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

31. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।
32. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।
33. अनुबंध-II के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी

क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

34. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है: "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

35. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जब तक पहले समाप्त न कर दिया जाता है, तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

36. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-2 (4) के अनुसार ऐसे सूचकों पर विचार किया है, जिनका प्रभाव उद्योग की स्थिति पर पड़ता है, जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि। इस संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति होने की संभावना की जांच करने से पहले, घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जांच करने की कार्रवाई की है।

मात्रा के प्रभाव

मांग और बाजार का हिस्सा

37. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योगफल के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार से मूल्यांकित मांग को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	शून्य	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि वार्षिकीकृत
मांग					
बिक्रियां – घरेलू उद्योग	मी.टन	***	***	***	***
बिक्रियां – अन्य घरेलू उत्पादक	मी.टन				
चीन	मी.टन	806	441	581	392
अन्य देश	मी.टन	308	478	301	200
कुल मांग/खपत (सीमा)	मी.टन	2000-2500	2000-2500	2000-2500	2000-2500
मांग में बाजार का हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	19.23%	24.84%	27.77%	35.16%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	28.18%	30.45%	34.66%	35.14%

चीन	%	38.05%	21.47%	24.76%	19.65%
अन्य देशों के आयात	%	14.55%	23.25%	12.28%	10.04%
कुल हिस्सा	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में मामूली गिरावट आई है।

आयातों की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

39. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के रूप में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

40. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार आंकड़ों पर विचार करने के बाद क्षति अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
आयात की मात्रा					
चीन	मी.टन	806	441	581	392
अन्य देश	मी.टन	308	478	301	200
कुल आयात	मी.टन	1,114	919	882	592
आयातों में बाजार का हिस्सा					
चीन	%	72%	48%	66%	66%
अन्य देश	%	28%	52%	34%	34%
संबद्ध देश के आयात के संबंध में					
घरेलू उद्योग के संबंध में	%	196%	87%	91%	54%
भारतीय उत्पादन के संबंध में	%	80%	39%	40%	27%
घरेलू उद्योग की विक्रियों के	%	198%	86%	89%	56%
भारतीय मांग के संबंध में	%	38%	21%	25%	20%

41. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों में गिरावट आई है। लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क के कारण क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों के संबंध में चीन से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क के कारण उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी गिरावट आई है, लेकिन मांग और उत्पाद के संबंध में आयातों का हिस्सा अभी भी अत्यधिक बना हुआ है।

पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और उसका घरेलू उद्योग पर प्रभाव

42. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री होने के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना, संबद्ध देश से आयातों के पहुंच के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की तुलना, पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग कीर निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करों, छूटों, डिस्काउंट्स और घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए जा रहे कमीशन का समायोजन किया गया है। प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत का आकलन किया है और उसकी तुलना पहुंच मूल्य के

साथ की है। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उचित रूप से विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन किया गया है। इसकी स्थिति निम्नानुसार है:-

कीमत-कटौती

43. प्राधिकारी ने कीमत कटौती का विश्लेषण किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	368.52	482.31	585.19	666.62
निवल विक्री कीमतम	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	30-40%	10-20%	5-15%	(0)-10%

44. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से कीमत कटौती मासूली सकारात्मक है।

कम कीमत पर विक्री

45. नीचे तालिका से यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में चीन से आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर नहीं बेचे जा रहे हैं।

विवरण	रूपए/कि.ग्रा.	\$/कि.ग्रा.
क्षति रहित कीमत	***	***
पहुंच मूल्य	667	9.94
कम कीमत पर विक्री	(***)	(***)
कम कीमत पर विक्री की सीमा %	(0)-(10)	(0)-(10)

पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव

46. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में दबाव पड़ रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि वार्षिकीकृत
विक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	109	112
विक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	120	125

47. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत और विक्री कीमत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयात, घरेलू बाजार में कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

48. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II में उल्लिखित प्रावधान में क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच करना निहित है। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का तथ्य

परक और निष्पक्ष जांच करना शामिल है, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनमें विक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाठन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता भी शामिल है।

49. तदनुसार घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक प्राचलों का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्रियां

50. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	1,140	1,140	1,140	1,140
उत्पादन	मी.टन	411	509	641	698
क्षमता उपयोग	मी.टन	36%	45%	56%	61%
कुल विक्रियां	मी.टन	407	511	651	701

51. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी हुई है। क्षति अवधि के दौरान चीन से पाटिं आयातों पर लागू पाठन-रोधी शुल्क के प्रभाव के रूप में उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन क्षमता का अभी भी कम उपयोग हो रहा है।

माल सूचियां

52. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का औसत मालसूची स्तरों में गिरावट आई है, लेकिन विगत वर्ष से जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि वार्षिकीकृत
स्टॉक (मात्रा)					
प्रारंभिक	मी.टन	14	18	16	15
अंतरेष्ट	मी.टन	18	16	6	13
औसत	मी.टन	16	17	11	14

लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

53. क्षति अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि वार्षिकीकृत
विक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	109	113
विक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	120	124
लाभ/(हानि)	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-36	20	29

लाभ/(हानि) - कुल	लाख रूपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-45	32	50
मूल्यहास	लाख रूपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	108	167
नकदी लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-41	42	65
ब्याज	लाख रूपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	92	94	196
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-28	78	140
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ सीमा %	%	0-(10)%	0-(10)%	0-10%	5-15%

54. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक घरेलू उद्योग को घाटे हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वह अपने लाभ में वृद्धि करने में सक्षम हुआ है और उसे वर्ष 2015-16 और जांच अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में भी वृद्धि होने की प्रवृत्ति बनी हुई है।

रोजगार और वेतन

55. नीचे तालिका से यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में रोजगार में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान वेतन में सुधार हुआ है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	82	99	115	125
वेतन	लाख रूपए	66	95	158	177
वेतन प्रति यूनिट	रूपए/कि.ग्रा.	16	19	25	25

पाठन की मात्रा

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों का पाठन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है।

विवरण	रूपए/कि.ग्रा.	\$/कि.ग्रा.
क्षति रहित कीमत	***	***
पहुंच मूल्य	***	***
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन %	15-25%	15-25%

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

57. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना, जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए चीन से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार से आकलित निर्यात मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	रूपए/कि.ग्रा.	\$/कि.ग्रा.
1	क्षति रहित कीमत	***	***
2	पहुंच मूल्य	667	9.94
3	क्षति मार्जिन	***	***
4	क्षति मार्जिन %	(0)-(10)%	(0)-(10)%

क्षति पर निष्कर्ष

58. जांच से यह पता चला है कि हालांकि चीन से आयातों में गिरावट आई है, लेकिन पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद ये भारत में समग्र रूप से तथा उत्पादन/खपत के संबंध में अभी भी अत्यधिक बने हुए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के फलस्वरूप क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। उत्पादन, विक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

59. प्राधिकारी ने अन्य कारकों से यदि कोई क्षति हुई है, तो उसको पृथक करने के लिए नियमावली में यथा निर्धारित कारणात्मक संबंध होने और अन्य गैर-आरोपित कारकों के मुद्रे की जांच की है। इस संबंध में नियमावली में यथा निर्धारित निम्नलिखित निर्देशात्मक कारकों की जांच की गई है।

त्रीतीय देशों से आयात

60. प्राधिकारी ने कारोबार-वार आधार पर डीजीसीआईएंड से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, चूंकि वर्तमान जांच, निर्णायिक समीक्षा जांच है, इसलिए वर्तमान जांच में नए देशों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

खपत के पेटर्न में परिवर्तन

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान खपत के पेटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पेटर्न में संभावित परिवर्तन, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

मांग में संकुचन

62. हालांकि संबद्ध वस्तुओं की मांग में मासूली गिरावट आई है, लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित क्षमता के लिए पर्याप्त मांग है। इस प्रकार मांग में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

प्रोद्योगिकी में विकास

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रोद्योगिकी में विकास को एक ऐसा कारक नहीं माना जा सकता है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

प्रतिस्पर्श की दशाएं और व्यापार की प्रतिबंधित पद्धतियां

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की ऐसी कोई प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हो सकती है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

65. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और यह संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने का परिणाम है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादकता में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ज. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और उनकी पुनरावृति होने की संभावना

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

66. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना के अपने दावे के समर्थन में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों के बावजूद निरंतर पाटन हो रहा है और उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- (2) मूल जांच में संबद्ध देश के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन से संबद्ध देश से उत्पादकों की पाटन की प्रवृत्ति का पता चला है।
- (3) संबद्ध देश से निर्यातिक अनेक वर्षों से पाटन की सामान्य पद्धति अपना रहे हैं और वे न केवल भारत में बल्कि तृतीय देशों में भी पाटन कर रहे हैं। संबद्ध देश में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तुओं के व्यापक उत्पादन क्षमताएं हैं। मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारत में उत्पाद के पाटन की प्रबल संभावना है।
- (4) व्यापक उत्पादन क्षमताएं होने के अतिरिक्त संबद्ध देश में उत्पादकों का अधिक निर्यात प्रतिशत है।
- (5) संयुक्त राज्य अमरीका ने भी एक दशक से चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए हुए थे। संयुक्त राज्य अमरीका में पाटन-रोधी शुल्क वर्ष 2015 में समाप्त कर दिए गए थे और उसके तत्काल बाद संयुक्त राज्य अमरीका में चीन से तेजी से आयात होने शुरू हो गए थे। संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारी ने यह माना था कि पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उद्योग में परिवर्तन हुआ था और उसके प्रचालन का कार्य-क्षेत्र सीमित था। इस पर भी बल दिया गया था कि चीन के संबद्ध उत्पादकों के पास अतिरेक क्षमता है और वे निर्यातोन्मुख हैं।
- (6) घरेलू उद्योग को कुछ समय से पाटित आयातों से क्षति हो रही है, जैसा कि मूल जांच के साथ-साथ मध्यावधि और विगत निर्णायक समीक्षा जांच के समय उसकी संपुष्टि हुई है। घरेलू उद्योग पाटित आयातों की क्षति से असुरक्षित है। वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क एक प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है और ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना और बढ़ जाएगी।
- (7) घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद को चीन जनवादी गणराज्य से अनेक अन्य देशों को किए जा रहे नियति की कीमत से अधिक कीमत पर बेच रहा है। इसलिए शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निर्यातिक अपने उत्पादन को भारतीय बाजार में सरणीबद्ध कर देंगे क्योंकि उनके पास अतिरेक क्षमताएं विद्यमान हैं और वास्तव में वे तृतीय देशों में संबद्ध वस्तुओं को पाटित कीमतों पर बेच रहे हैं।
- (8) पाटन-रोधी शुल्क नहीं होने पर चीन से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती होगी।
- (9) संयुक्त राज्य अमरीका में पाटन-रोधी शुल्क वर्ष 2015 में समाप्त कर दिए गए थे और उसके तत्काल बाद संयुक्त राज्य अमरीका में चीन से तेजी से आयात होने शुरू हो गए थे। इससे चीन में उत्पादकों की पाटन करने की प्रवृत्ति का पता चलता है। इस प्रकार इस पर विचार करना उचित है कि कि निर्यातिक अत्यधिक मात्रा में विक्री करके पाटन करेंगे और संबद्ध देश घरेलू बाजार में पुनः प्रवेश करने के लिए पाटन करना शुरू कर दे।
- (10) जांच अवधि के साथ-साथ जांच पश्चात अवधि में निर्धारित पाटन मार्जिन से पता चलेगा कि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है, लेकिन वे पाटित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। जांच अवधि के लिए निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नकारात्मक है, लेकिन जांच पश्चात अवधि के लिए निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
- (11) निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में घरेलू उद्योग की क्षति की जांच उस तरीके से नहीं की जा सकती है, जैसा कि मूल जांच के चरण में किया जा रहा है। निर्णायक समीक्षा जांच के चरण में नियम 11 (अनुबंध-2 के साथ पठित) को कड़ाई से लागू करना अनुपयुक्त है। अनुबंध-2 के पैरा (7) में सूचीबद्ध प्राचल पारस्परिक रूप से समाविष्ट नहीं है, जिसका यह अभिप्राय है कि मूल जांच में भी उपरोक्त सूचीबद्ध किसी भी प्राचल के निष्फल होने पर प्राधिकारी

आर्थिक क्षति के खतरे पर सकारात्मक परिणाम देने से स्वयं को प्रतिवंशित नहीं करेंगे, यदि विद्यमान अन्य प्राचलों से अन्यथा सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त खतरे के प्राचलों की सूची व्यापक नहीं है और यह निर्देशात्मक मात्र है।

(12) ऐसे आयात कारोबार जिनके आयात की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम है, पर मात्र विचार करते हुए संभावित प्रयोजन के लिए कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में यूरोपीय समुदायों – ब्राजील से मेलेबल कॉस्ट आयरन ट्यूब अथवा पाईप फिटिंग्स और कोठारी शुगर्स इंड केमिकल्स लिमिटेड पर पाटन-रोधी शुल्क बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले पर विश्वास किया गया है।

(13) याचिका में निर्यातोन्मुखीकरण, बेशी क्षमता और संभावना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ज. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

67. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के बारे में कोई निवेदन नहीं किया है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

68. वर्तमान जांच, आयातों पर पहले से लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णयिक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लागू किया गया शुल्क का अभीष्ट उद्देश्य क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दूर करना है। इस मामले में चूंकि चीन से निरंतर पाइट आयात हो रहे हैं, प्राधिकारी को इसकी जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप उत्पाद का निरंतर पाटन होता रहेगा और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होगी और क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन की पुनरावृति की संभावना होगी और उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी।

69. वर्तमान जांच में चूंकि संबद्ध देश से निरंतर पाइट आयात हो रहे हैं, प्राधिकारी को इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन की पुनरावृति होगी। लागू किए गए पाटन-रोधी उपायों के बावजूद भी संबद्ध देश भारतीय बाजार में अत्यधिक मौजूदगी बनाए हुए हैं और संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है, लेकिन वर्तमान क्षति अवधि में वे समग्र रूप से अत्यधिक बने हुए हैं। हालांकि विभिन्न आर्थिक प्राचलों के विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुधार मुख्यतया लागू पाटन-रोधी उपायों के कारण हुआ है। प्राधिकारी ने इन प्राचलों पर विचार करते हुए क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना की जांच की है, जो कि निम्नोक्त अनुसार है:

(क) वर्तमान और पाटन पश्चात मार्जिन का स्तर

70. विगत जांचमें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और अब मूल्यांकित पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए ऐसा स्पष्टतया पता चलता है कि चीन से पाइट कीमतों पर निरंतर निर्यात किए जा रहे हैं और पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर देने से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बाद आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन वह अभी भी अत्यधिक बनी हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात आधार वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत घटा है।

(ख) जांच अवधि पश्चात निर्यातों की मात्रा

71. प्राधिकारी ने यह देखने के लिए कि निर्यात की मात्रा से ऐसी कोई अन्य भिन्न प्रवृत्ति दिखाई देती है जिस पर प्राधिकारी विचार कर सके, जांच की अवधि के दौरान (अक्टूबर, 2016 – सितंबर, 2017) संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों के निर्यात की मात्रा का विश्लेषण किया है। यह पाया गया है कि चीन से आयात वार्षिक जांच की अवधि (392 मी. टन) की तुलना में जांच की अवधि के बाद के दौरान बढ़े हैं। चीन से आयात उत्पाद के सामान्य मूल्य से कम पाए गए थे। आयात कीमतों में माह-वार उत्तर-चढ़ाव सामने आया है, यहां तक कि जब सामान्य रूप से वे जांच की अवधि के बाद के दौरान कम हुए हैं। यह आयात की संभावना दर्शाता है जिससे पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में काफी कटौती तथा घरेलू बाजार में मूल्यहास हुआ है। तथापि, यह सीमित जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के साथ निष्कर्ष रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता।

जांच अवधि पश्चात (अक्टूबर, 2016 – मार्च, 2017) चीन से आयात – डीजीसीआईएंडएस

क्रमांक	विवरण	कुल आयात (मी.टन) (अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017)	पाइट आयात की मात्रा मी.टन (अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017)
1	आयात की मात्रा (जांच अवधि पश्चात)	568.200	502.20
2	आयात का मूल्य लाख रूपए (जांच अवधि पश्चात)	2886.01	2461.84
3	सीआईएफ (आयात कीमत प्रति कि.ग्रा. - जांच अवधि पश्चात)	507.90	490.21
4	सीआईएफ (आयात कीमत प्रति कि.ग्रा. - जांच अवधि)	613	613

क्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(ग) जांच अवधि पश्चात पाठन और क्षति मार्जिन

72. प्राधिकारी ने जांच अवधि पश्चात संबद्ध देश से पाठन और क्षति मार्जिन का विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों के आधारपर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि पश्चात पाठन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है। पाठन की मात्रा में बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई है जो जांच की अवधि के बाद की अवधि के अंत में लगभग दोगुनी हुई है। तथापि, जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों से निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है।

73. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि पश्चात विश्लेषण भी किया है। यह पाया गया है कि औसत क्षति मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है और मासिक-वार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर प्रथम चार महीनों में नकारात्मक क्षति की विशेष प्रवृत्ति और उसके बाद क्षति में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता चला है, जो कि 2-36% के बीच है।

(घ) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

74. भारत में चीन से संबद्ध वस्तुओं को जिस कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, वह पाठन के निरंतर जारी रहने की संभावना की सूचक है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को चीन जनवादी गणराज्य से अनेक अन्य देशों को किए जा रहे निर्यात की कीमत से अधिक कीमत पर बेच रहा है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने चीन से तृतीय देशों को निर्यात कीमत के रूप में साध्य प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि चीन से तृतीय देशों को निर्यातों के संबंध में पाठन मार्जिन अत्यधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने तृतीय देशों में पाठन के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदनों का खंडन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे का खंडन करने के लिए किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने कोई विपर्यय साध्य प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल भारतीय मांग प्रतिवर्ष लगभग 2000 मी.टन रही है और संबद्ध देश से निर्यातकों के लिए यह काफी नहीं है।

(ङ) चीन के उत्पादकों की बेशी क्षमता और निर्यात उन्मुखीकरण

75. जबकि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और मौजूदा बेशी क्षमताओं, क्षमताओं में आसन्न वृद्धि होने और वर्तमान निर्यातों के एक देश से दूसरे देश को परिवर्तित कर दिए जाने के बारे में कोई सत्यापन योग्य साध्य और सूचना प्रस्तुत नहीं की है, घरेलू उद्योग ने चीन में उत्पादकों के पास व्यापक क्षमताएं होने और उनके निर्यातोन्मुखी होने के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। यह देखा गया है कि चीन में विशिष्ट उत्पादकों की क्षमता भारत में समग्र मांग से काफी अधिक है। संयुक्त राज्य अमरीका में शुल्क को समाप्त करने पर आयातों में उद्घाल आने से ऐसा पता चलता है कि चीन के उत्पादकों की कीमत आकर्षक गंतव्य स्थानों को आयातों को अपवर्तित करने की क्षमता है। संयुक्त राज्य अमरीका के

प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2015 में शुल्क को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने यह माना था कि पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, घरेलू उद्योग को क्षति होने का पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उद्योग में परिवर्तन हुआ था और उसके प्रचालनों का कार्य-क्षेत्र सीमित था।

कंपनी का नाम	मी.टन प्रति वर्ष
मेसर्ज टिआन्जिंग केमिकल कंपनी	3500
मेसर्ज केर्डेंग किसनघुआ केमिकल फैक्टरी	7000
मेसर्ज केर्डेंग किसनघुआ फार्इन केमिकल लिमिटेड	15000

स्रोत: संबद्ध कंपनियों की वेबसाइट

प्रयोक्ता उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

76. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाठियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाना किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात को प्रतिवंशित करना और उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित करना नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग का हिस्सा बढ़ा है परंतु आयात भी लगभग 30 प्रतिशत बाजार हिस्से में जारी रहे हैं। इस प्रकार, उपभोक्ताओं ने दो या दो से अधिक आपूर्ति स्रोत बनाए रखे हैं।

अ.1 घरेलू उद्योग के विचार

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात किए गए अधिकतर निवेदन पुनरावर्तक प्रकृति के हैं और इनका समाधान पहले से ही प्रकटन विवरण में कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में चीन से किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि की गई प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में विभिन्न उत्तर प्रस्तुत किए गए थे।
- (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर किया गया है। यह निवेदन है कि उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करने की आवश्यकता है और न कि सामान्य मूल्य की संरचना के लिए कालिप्त लागत पर।
- (ग) घरेलू उद्योग पाटन के विगत दुष्प्रभाव से उभर रहा है, लेकिन वह अभी भी पाटन से असुरक्षित बना हुआ है।
- (घ) केवल ऐसी परिस्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब सभी स्थितियों में क्षति मार्जिन नकारात्मक होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मान सकते हैं कि भारतीय बाजार, विदेशी उत्पादकों का आकर्षित नहीं कर रहा है तथा पाटन और क्षति होने की संभावना नहीं है।
- (ङ) जांच अवधि पश्चात चीन से आयातों में वृद्धि हुई है और जांच अवधि पश्चात आयात कीमत में तेजी से गिरावट दृष्टिगत हुई है, जिसमें हाल ही की अवधि में और गिरावट आई है। इसके परिणाम स्वरूप हाल ही की अवधि में अर्थात् सितंबर, 2017 में कच्चे माल की कीमतों में समान गिरावट आए बिना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी गिरावट आई है।
- (च) चीन जनवादी गणराज्य चीन से उत्पादक और निर्यातक अन्य देशों के बाजारों में पाटित और क्षति कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात कर रहे हैं।
- (छ) संबद्ध देश में उत्पादकों के पास व्यापक क्षमताएं उपलब्ध हैं।
- (ज) संयुक्त राज्य अमरीका ने भी एक दशक तक चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया था। संयुक्त राज्य अमरीका में वर्ष 2015 में पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए गए थे और उसके तत्काल बाद संयुक्त राज्य अमरीका में चीन से आयातों में उछाल आ गया था।
- (झ) शुल्क निर्धारित रूप में लगाए जाने चाहिए और उन्हें अमरकी डालर में निश्चित किया जाना चाहिए।

ज. 2 उत्पादकों/नियर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

78. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात किए गए अधिकतर निवेदन पुनरावर्तक प्रकृति के हैं और इनका समाधान पहले से ही प्रकटन विवरण में कर दिया गया है तथा इसका पुनः समाधान अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना में उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत किया गया है। इसके बावजूद प्राधिकारी ने जितना प्रासंगिक समझा गया था, इन मुद्दों का समाधान कर दिया है, जो कि निम्नानुसार है:-

- (क) सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में मानक पद्धति का अनुसरण किया गया है और अनुसरण की गई कार्य-प्रणाली से विचलन करने की कोई योग्यता नहीं है।
- (ख) शुल्क के रूप के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार शुल्क के रूप पर विचार किया जाता है। वर्तमान मामले में शुल्क पहले से ही अमरीकी डालर के रूप में सुनिश्चित कर लागू किए गए हैं और ऐसा उचित समझा गया है कि इन्हें निरंतर जारी रखा जाए।

ठ. निष्कर्ष

80. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. यद्यपि पाटन है, परंतु पाटनरोधी मार्जिन के स्तर पूर्व जांच की अवधि की तुलना में वर्तमान जांच की अवधि में कम हुए हैं। विचाराधीन उत्पाद के पाटन के बावजूद क्षति मार्जिन जांच की वर्तमान अवधि में नकारात्मक पाया गया है।
- ii. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों से नीचे नहीं बेचा जा रहा है और संबद्ध देश से जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती लागू पाटनरोधी शुल्क के बिना केवल आंशिक रूप से सकारात्मक है।
- iii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा और लाभ के संदर्भ में सुधार आया है। निवेश आय, नकद लाभ आदि में भी आधार वर्ष की तुलना में समान रूप से सुधार आया है।
- iv. कुल आयात के संबंध में चीन से आयात का हिस्सा क्षति की अवधि में और भी घटा है; उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयात कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और निवल बिक्री वसूली में वृद्धि हुई है जिससे संबद्ध देश से पाटन के कारण होने वाली क्षति में कमी आई है।
- v. प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों को भी ध्यान में रखा है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क 06 जून, 2006 से लागू है।
- vi. जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण निर्मित सामान्य मूल्य तथा वर्तमान जांच की क्षति रहित कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया था तथा माह वार विश्लेषण के दौरान स्थिर रखा गया था। सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के बाद के दौरान भी परिवर्तित हो सकती है, यदि अन्य कारक ध्यान में रखे जाएं। अतः पाटित आयातों की संभावना तथा परिणामस्वरूप प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की अवधि के बाद की जांच के आधार पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति निष्कर्ष रूप से निर्धारित करना कठिन है।
- vii. तीसरे देश के नियर्यात तथा नियर्यातकों की स्टॉक माल सूची सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि किसी भी नियर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है तथा अपेक्षित आंकड़े नहीं दिए हैं। चीनी उत्पादकों की नियर्यातोन्मुखता तथा भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को नोट करते समय यह भी महसूस किया गया है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्द्धि का सामना करने के लिए बेहतर स्थान होगा क्योंकि उसका अब 70 प्रतिशत बाजार हिस्सा है।
- viii. विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण घरेलू उद्योग की समग्र आर्थिक स्थिति दर्शाता है जिसमें जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुधार मुख्य रूप से लागू पाटनरोधी उपायों के कारण है। पाटनरोधी उपायों से नियर्यातकों द्वारा उनके सामानों के पाटन से कार्यान्वयन अनुचित लाभ को कम करने का इच्छित प्रयोजन पूरा हुआ है।

ix. प्राधिकारी यह भी दोहराते हैं कि भारत पाटनरोधी सुधारात्मक उपाय लगाने के लिए निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कम शुल्क नियम अपनाता है। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः पाटनरोधी व्यापार सुधारात्मक उपाय केवल पाटन के आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते।

ड. सिफारिशें

81. यह पाए जाने पर कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 06 जून, 2006 से अस्तित्व में है, प्राधिकारी का यह मत है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से इच्छित प्रयोजन पूरा हुआ है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और 07 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना 15/20/2010-डीजीएडी द्वारा सिफारिश किए गए तथा 13 जनवरी, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना 7/2012-सीमा शुल्क द्वारा लागू तथा केंद्र सरकार द्वारा 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 03/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा बढ़ाए गए अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क बंद करने की सिफारिश करते हैं।

ड. आगे की कार्रवाई

82. केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2017

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset review (SSR) investigation of the anti-dumping duties imposed on the imports of Saccharin from China PR

F. No. 15/23/2016-DGAD.—(Case No. SSR 03/2017): Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the AD Rules).

A. Background of the case

- Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of “Saccharin” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No 14/27/2004-DGAD dated 4th July 2005, into alleged dumping of Saccharin from China PR and consequent injury to the domestic industry.
- And whereas, preliminary findings were issued on 1st April 2006 vide Notification No 14/27/2004-DGAD and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 54/2006-Customs dated 6th June 2006. Subsequently, final Findings were issued on 3rd January 2007. Definitive antidumping duties were imposed, vide Ministry of Finance Notification 41/2007-Customs, dated 19th March 2007, on the imports of Saccharin (hereinafter referred to as the subject goods) from China PR (hereinafter referred to as the subject country).
- And whereas, the Authority conducted a Mid Term Review (MTR) and recommended modifications of the duties vide the Findings Notification No 15/15/2008-DGAD dated 6th November 2009. The modified duties were imposed by the Central Government vide Custom Notification No. 136/2009 dated 9th December 2009.
- And whereas, subsequently the Authority initiated a sunset review of the above antidumping duty vide

notification dated 31st May, 2010 and recommended continued imposition of definitive antidumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the above country, vide Final Finding Notification No. 15/20/2010- DGAD dated 7th December 2011 and the duties were extended, vide Customs Notification No. 7/2012-Cus dated 13th January 2012, for a further period of 5 years i.e., till 12th January 2017.

5. And whereas, a duly substantiated application was filed by M/s Swati Petro Products Pvt. Limited, M/s Shree Vardayini Chemical Ind. Pvt. Ltd. and M/s A S Chemoparma Pvt. Limited (hereinafter referred to as ‘applicant’), in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of Saccharin for extending the duties for a further period of 5 years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods originating in or exported from the above country and consequent injury to the domestic industry.
6. Having satisfied that the applicants have substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. F.No.15/23/2016-DGAD dated 10th January, 2017. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended up to 12th January 2018 by the Central Government vide Notification No. 3/2017-Customs (ADD) dated 19th January, 2017.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

8. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - i. The Authority issued a public notice F.No.15/23/2016-DGAD (Case No. SSR 03/2017) dated 10th January 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
 - ii. The Authority sent copy of the initiation notification dated 10th January, 2017 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses along with market economy treatment responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of China along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time limit.
 - iii. The copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicants was made available to the known exporters, other domestic producers and the embassy of China in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters/representative organizations in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rules:
 - a) Suzhou Fine Chemicals Group Company Ltd
 - b) Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd.
 - c) Kaifeng Xinghua Fine Chemical Factory
 - d) Tianjin North Food Co. Ltd.
 - e) Tianjin Changjie Chemical Co. Ltd.
 - f) PMC Beijing Chemical Co. Ltd.
 - v. However, no questionnaire response was received from any exporter/ producer of the subject goods from the subject country.
 - vi. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification along with Importer’s Questionnaires to

the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4).:

- a) Eagle Trading company
- b) Colgate Palmolive India Ltd.
- c) General Import Co India
- d) Jagmohandas & Sons
- e) Speciality Chemicals
- f) C J Shah &. Co.
- g) Grauer & Well India Ltd.
- h) Nandlal Bankatlal Pvt. Ltd.
- i) Nectar Drugs P. Ltd
- j) Procter & Gamble Hygiene And Health
- k) Sun Shine Cosmetics Ltd.
- l) Neeru Marketing P. Ltd.

vii. However, no questionnaire response was received from any importer of the subject goods.

viii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).

ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.

x. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if antidumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Antidumping Rules.

xi. Period of Investigation in the instant investigation is July 2015- September 2016 (15 months). The injury investigation period covered is 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the Period of Investigation (POI).

xii. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.

xiv. The Authority held an oral hearing on 2nd November, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). Only domestic industry and its representative attended the oral hearing. The domestic industry was advised to file written submissions of the views expressed orally. The Authority has considered submissions received from the domestic industry appropriately.

xv. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 6th December, 2017.

The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry has been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

- xvi. ***represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xvii. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 67.06 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this investigation.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by the Domestic Industry

9. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the product under consideration (PUC):

- i. The product under consideration is “Saccharin” in all its form originating in or exported from China PR
- ii. The Designated Authority in its last conducted investigation on subject goods held as follows in regard to product under consideration:

“Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation. Being a sun set review; the PUC is the same as in the earlier investigations.”

Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 29251100. The domestic industry claimed imports of subject goods under several other tariff sub-headings as well, which has been examined below. However, the Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigations.”

- iii. Present petition being a sunset review petition, product under consideration remains the same as defined in the original investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.
- iv. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods imported into India. Saccharin produced by the domestic industry and imported into India are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

Submissions by the exporters/importers/other interested parties

10. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the product under consideration.

Examination by the Authority

11. The product under the present investigation is ‘Saccharin ’In the original investigation, the product under consideration was defined as follows:

“The product under consideration (PUC) in the present investigation is Saccharin originating in or exported from China PR. Saccharin is a nonnutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation. Being a sunset review; the PUC is the same as in the earlier investigations.”

“Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 29251100. The domestic industry claimed imports of subject goods under several other tariff sub-headings as well, which has been examined below. However, the Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigations.”

12. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of original investigation. Moreover, none of the interested parties have made any submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.
13. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions by the Domestic Industry

14. The domestic industry has made following submissions in this regard:
 - i. The Applicants are major producers of the like article in India. Production by applicants accounts for “a major proportion” of the domestic production. The petition is supported by Blue Circle Organics Pvt. Ltd.
 - ii. The applicants have not imported the subject goods from subject country during the period of investigation. Further, applicants are not related to any exporter or producer of the investigation. Further, applicants are not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or an importer or user of the product under consideration in India.
 - iii. Without prejudice to the legal position that the present investigations being sunset review investigations, the Authority is not required to ascertain standing of the applicants to file the present petition, the petition satisfies the requirement of standing under the Rules and applicants constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

Submissions made by the exporters/importers/other interested parties

15. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the scope and standing of the Domestic Industry.

E .Miscellaneous Submissions

16. At the very later stage of investigation, M/s Sandeep organics stated vide email dated 21.11.2017 that they have sent the submission, but they have not received any correspondence from the Authority.

Examination by the Authority

17. The petition has been filed by M/s Swati Petro Products Pvt. Limited, M/s Shree Vardayini Chemical Ind.

Pvt. Ltd. and M/s A S Chemoparma Pvt. Limited. Blue Circle Organics Pvt. Ltd has supported the petition. Applicant companies have neither imported the subject goods nor are they related to any producer of subject goods in subject country or to an importer of subject goods. The production of the applicant companies constitutes more than 50% of Indian production. Applicants constitute the domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Thus, the applicants are being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

18. The Authority examined the contentions of M/s Sandeep Organics and found that as per its records M/s Sandeep Organics is not an interested party, further they have neither filed any response, nor they have participated in the investigation proceedings. Authority communicated the same to M/s Sandeep Organics and further advised them to submit evidence/ proof of their claim. Moreover, an opportunity of personal hearing was also granted by the investigation team to them, but they failed to avail the same. Consequently, no evidence/proof regarding their claim was submitted by them to the Authority. Therefore, the Authority has rejected their claim.

E. NORMAL VALUE EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

19. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

20. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producer/ exporter from subject country have co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses.

E.1 Submissions made by the Domestic Industry

21. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. Applicants have constructed normal value based on best available information.
- ii. The investigation period considered by the Authority in the present case is July 2015 to September 2016 (15 months). The injury investigation period has been considered as the period 2013-14, 2014-15 and POI.
- iii. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.
- iv. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also

implies that unless these conditions are not fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.

- v. The consideration of market economy status is based on parameters prevailing during investigation period. Since the reason for rejection of Chinese costs and prices is distortion in the costs and prices in China due to the factors listed in Para 8 to Annexure-I, applicants submit that it is the investigation period that is relevant to decide consideration of Chinese producers as market economy companies.
- vi. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, applicants submit that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.
- vii. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.
- viii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- ix. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The applicants have claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- x. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period.

E.2 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested Parties

22. None of the other interested parties have made any submissions with regard to normal value, export price and dumping margin.

E. 3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Market Economy status for Chinese producers

23. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - i. *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

b) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

24. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is June 2015 to September 2016. Since the sub-paragraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

25. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

26. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 to prove market economy status. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:

- a) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values.
- b) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.
- c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

27. It is noted that none of the producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment, as none of the producer/exporter from China PR have responded in the present investigation. Accordingly, the authority is not required to examine any of the above criteria for Chinese Producers and holds that producers/exporters from China PR are not operating under market economy conditions and therefore, has adopted the constructed normal value for determination on normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.

E.4. Determination of Export Price

28. The Authority had sent questionnaire to the known producers/exporters of the product in China and also the Government of China. However, no questionnaire response has been received by the Authority from any producer or exporter of the subject goods in China. The Authority has, therefore, not been able to

determine dumping margin in respect of producers/exporters from China on the basis of questionnaire response from the concerned producers/exporters. Export price in case of all producers in China has been determined on the basis of import data procured from DGCI&S. The export price has been determined on the basis of weighted average import price from DGCI&S. Price adjustments have been made on account of inland freight, overseas freight, international insurance, bank charges, port charges and VAT as per best available information on record in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level has been determined, which is indicated in the Table below:

SN	Particulars	UOM	POI
1	Import volume	MT	490
2	Import value	Rs. Lacs	3,003
3	CIF Value	Rs/Kg	613
4	Freight (50USD)/MT	Rs/Kg	***
5	Insurance (0.5%)	Rs/Kg	***
6	FOB Price	Rs/Kg	***
7	Commission	Rs/Kg	***
8	Bank Charge	Rs/Kg	***
9	Handling Charge	Rs/Kg	***
10	Port expenses	Rs/Kg	***
11	VAT @ 4%	Rs/Kg	***
12	Net Export price	Rs/Kg	***

E.5. DUMPING MARGIN

29. The export price of China to India has been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from China has been determined as provided in the table below:

Particulars	Rs./kg	\$/KG
Constructed Normal value	***	***
Net export price	***	***
Dumping margin	***	***
Dumping margin %	15-25%	15-25 %

F. INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Submissions made by the domestic industry

30. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. The demand of the product concerned in India has shown a positive trend.

- ii. Imports from China have slightly declined the injury period. This decline is on account of the existing anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject country. In an event the anti-dumping duty is revoked, the volume of imports will increase as the producers in China have huge quantity and due to their orientation to export the major proportion of subject goods.
- iii. Subject imports are significant in terms of demand and production in India; Market share of subject imports in total imports is significant in the proposed POI.
- iv. Imports from the subject country are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market. There existed a significant price undercutting in the injury period.
- v. Both, costs of sales and selling price have increased throughout the injury period, thus there is no price suppression or depression effect. However, the landed price of imports have remained below the level of costs of sales and selling price. Thus in the event of revocation of duties, the imports from subject country is likely to cause suppressing effect on domestic industry's price.
- vi. A comparison of landed price of imports, considering the prices being offered by the Chinese producers, with the cost of production of the domestic industry shows that the cessation of anti-dumping duty shall lead to significant price underselling in the market.
- vii. The performance of the domestic industry has improved in terms of production and sales volume. However, dumped imports still capture a significant portion of the Indian market. This has resulted in sub-optimal volume of sales, production and under-utilization of capacity.
- viii. Profits, cash flow and return on capital employed which were showing positive trends. However, the performance in terms of profitability was sub-optimal in the presence of dumped imports in the market. This clearly shows effect dumped imports can have on the profitability of the domestic industry.
- ix. Inventories with the Domestic Industry have been significant in the proposed injury period.
- x. The employment and wages with the domestic industry has increased over the injury period. These parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of dumping on the domestic industry
- xi. Production, sales, market share, profits, return on investment, cash profits, etc. has shown improvement since the base year. Further, the growth is significantly low in the presence of dumped imports from the subject country. Significant share in demand is still being captured by dumped imports
- xii. Dumping margin in previous sunset review was also 19.31%. Dumping margin during the proposed period of investigation remains significant. Thus, it can be clearly seen that the dumping margin is not only more than de-minimus but is substantial. In the event of cessation of antidumping duty, the dumping of the product under consideration from subject country would intensify

F.2 Submissions made by producers /exporters /importers /other interested Parties

31. None of the other interested parties have made any submissions with regard to injury and causal link.

F.3 Examination by the Authority

- 32. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules and has considered the submissions made by the other interested parties appropriately.
- 33. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

34. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows: "*The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*"

35. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

36. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

Volume Effect

Demand and market share

37. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below :

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI -A
Demand					
Sales-Domestic industry	MT	***	***	***	***
Sales-Other Domestic producers	MT	***	***	***	***
China	MT	806	441	581	392
Other countries	MT	308	478	301	200
Total Demand/consumption	MT	2,118	2,056	2,346	1,994
Market Share in Demand					
Domestic industry	%	19.23%	24.84%	27.77%	35.16%
Other Indian Producers	%	28.18%	30.45%	34.66%	35.14%
China	%	38.05%	21.47%	24.76%	19.65%
Other Countries imports	%	14.55%	23.25%	12.28%	10.04%
Total Share	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

38. The Authority notes that the demand for the product under consideration has marginally fallen in the POI as compared to base year as well as previous year.

Import volumes and share of subject country:

39. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country have been analyzed as under:
40. The import volumes and values for the injury period, considering the transaction wise data provided by DGCI&S are as under:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualized
Import Volume					
China	MT	806	441	581	392
Other Countries	MT	308	478	301	200
Total Imports	MT	1,114	919	882	592
Market Share in Imports					
China	%	72%	48%	66%	66%
Other Countries	%	28%	52%	34%	34%
Subject Country Imports in relation					
to DI Production	%	196%	87%	91%	54%
to Indian Production	%	80%	39%	40%	27%
to DI Domestic Sales	%	198%	86%	89%	56%
to Indian Demand	%	38%	21%	25%	20%

41. From the above information, the Authority notes that imports from China have decreased. The share of imports from China in relation to total imports has declined over the injury period due to antidumping duty imposed. Further, imports in relation to production and consumption have also decreased due to anti-dumping duty in force but still it has significant share of import in relation to demand as well as production.

PRICE EFFECT

Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry

42. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price underselling. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for the subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

Price undercutting

43. The Authority has made price undercutting analysis as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed price of imports	Rs./KG	368.52	482.31	585.19	666.62
Net Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	30-40%	10-20%	5-15%	0.1-1%

44. The price undercutting from subject country during POI is marginally positive.

Price Underselling

45. It is noted from the table below that imports from China are not underselling the prices of the domestic industry.

Particulars	Rs./kg	\$/KG
Non Injurious Price	***	***
Landed Value	667	9.94
Price Underselling	***	***
Price Underselling %	-5 to 5%	-5 to 5%

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

46. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI Annualized
Cost of sales	Rs /Kg	***	***	***	***
	Index	100	98	109	112
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	103	120	125

47. From the above information, the Authority notes that cost of sales and selling price of the domestic has increased over the injury period. Thus, imports are not suppressing or depressing the prices in the domestic market.

Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

48. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments.

49. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analysed herein below:

Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

50. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity, capacity utilization and sales are as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualized
Capacity	MT	1,140	1,140	1,140	1,140
Production	MT	411	509	641	698
Capacity Utilization	MT	36%	45%	56%	61%
Total Sales	MT	407	511	651	701

51. From the information given above, the Authority notes that the capacity with the domestic industry has remained constant. Production, sales and capacity utilization have increased over the injury period as an effect of anti-dumping duty in force on dumped imports from China, but the capacity is still underutilized.

Inventories

52. From the information given below, the Authority notes that the average inventory levels of the domestic industry have decreased over the injury period but there is an increase in POI from previous year.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualized
Stock (Volume)					
Opening	MT	14	18	16	15
Closing	MT	18	16	6	13
Average	MT	16	17	11	14

Profits, return on investment and cash flow

53. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualized
Cost of sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Profit/(Loss) per unit	Rs/Kg	***	***	***	***
Profit/(Loss) – total	Rs Lacs	***	***	***	***
Depreciation	Rs Lacs	***	***	***	***
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Interest	Rs Lacs	***	***	***	***
Profit before Interest and Tax	Rs Lacs	***	***	***	***
Return on Capital Employed-NFA	%	0 to -10%	0 to -10%	0 to 10%	5 to 15%

54. From the above information, the Authority notes that the domestic industry was suffering losses in 2013-14 and 2014-15 but have been able to increase its profits thereafter and have been profitable in 2015-16 and POI. Similarly, profit before interest, cash profit and return on investment have also followed the same trend.

Employment and wages

55. It is noted from the table below that the employment with the domestic industry have increased in the POI. The wages have improved over the injury period.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualized
No. of Employees	Nos.	82	99	115	125
Wages	Rs Lacs	66	95	158	177
Wages Per Unit	Rs/Kg	16	19	25	25

Magnitude of dumping

56. The Authority notes that the dumping margin of the imports from China is positive and substantial.

Particulars	Rs./kg	\$/KG
Constructed Normal value	***	***
Net export price	***	***
Dumping margin	***	***
Dumping margin %	15-25%	15-25%

Magnitude of Injury and Injury Margin

57. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from China for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

S.N.	Particulars	Rs./kg	\$/KG
1	Non Injurious Price	***	***
2	Landed Value	667	9.94
3	Injury Margin	***	***
4	Injury Margin %	0 to -10%	0 to 10%

*Landed value is exclusive of ADD in force.

Conclusion on injury

58. The investigation has thus shown that imports from China have declined but still remains significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India. It is thus apparent that the imposition of anti-dumping duties resulted in improvement in performance of the domestic industry during the injury period. The performance of the domestic industry improved in terms of production, sales, capacity utilization, profits and ROI.

G. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

59. The Authority examined the issue of causal link and other non-attributive factors as laid down in the Rules to segregate injury, if any, caused by other factors. In this regard, the following indicative factors as laid down in the Rules have been examined

Imports from third countries

60. The Authority has examined import data of the subject goods obtained from DGCI&S on transaction-wise basis and notes that imports from other countries have increased. However, present investigation being a sunset review investigation, fresh countries cannot be included.

Changes in the pattern of consumption

61. The Authority notes that there has been no change in the pattern of consumption during the injury period. Possible shift in change in pattern of consumption cannot be a reason for injury to Domestic Industry.

Contraction in demand

62. The demand for the subject goods has declined marginally. However, there is sufficient demand for the capacity built by the domestic industry. Thus, decline in demand has not caused injury to the domestic industry.

Developments in technology

63. The Authority notes that the Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic industry.

Conditions of competition and trade restrictive practices

64. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

Productivity of the domestic Industry

65. The productivity of the Domestic Industry has increased and the same is a result of an increase in the production of the subject goods. Therefore, it can also not be said that injury to the Domestic Industry has been caused by decline in productivity.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping And Injury

H.1 Submissions by the Domestic Industry

66. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. Despite existing anti-dumping duties, there is continued dumping and injury being caused to the domestic industry.
- ii. The dumping margins determined in respect of subject country in the original investigations indicated the propensity for dumping by the producers of the subject country.
- iii. The exporters from subject country are habitual to dumping practices since years and have been dumping not only into India but also to third countries. The producers in the subject country have large production capacities for the subject goods. In the event of cessation of existing anti-dumping duties, there is a strong likelihood of dumping of the product in India.
- iv. In addition to having large production capacities, the producers in the subject country have a high export percentage.
- v. USA had also levied anti-dumping duty on the import of Saccharin from China PR for a decade. The antidumping duties ceased in 2015 in USA and immediately imports surged from China to USA. The US Authority had held that there is likelihood of increase in dumped imports, however material injury to the domestic industry was not foreseeable as the domestic industry in USA had undergone a change and had limited scope of operations. It was also emphasized that the Chinese subject producers possess excess capacity and are export oriented.

- vi. The Domestic Industry suffered injury from the dumped imports for quite some time as confirmed at the time of original investigation as well as mid-term and previous sunset review investigations. The Domestic Industry is vulnerable to injury from dumped imports. Present anti-dumping duty is acting as a restraint, and cessation of such duty will further increase the likelihood of injury to the Domestic Industry.
- vii. Domestic Industry are selling in domestic market at prices higher than at which product concerned is being exported from China PR to a number of other countries. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding excessive capacities and are in fact selling subject goods to other third countries at dumped prices.
- viii. Imports from China would cause severe price undercutting to the prices of the Domestic Industry in the absence of anti-dumping duty.
- ix. The antidumping duties ceased in 2015 in USA and immediately imports surged from China to USA. This shows the tendency of producers in China to dump. Thus, it is reasonable to consider that exporters had to dump to sell at higher volumes, and the subject country has to resume dumping in order to re-enter the domestic market.
- x. The dumping margin determined for POI as well as post POI will show that the imports from subject country have declined, however are entering the market at dumped prices. Injury margin determined for the POI is negative, however injury margin determined for the post POI is positive
- xi. Examination of injury to the domestic industry at the stage of sunset review cannot be done in the same manner as is being done at the stage of original investigations. Strict application of Rule 11 (read with Annexure-II) is inappropriate at the stage of sunset review. Parameters listed in Para (vii) of Annexure II are not mutually inclusive, meaning thereby, if any of the parameter listed above fails to exist, even in an original investigation, the Authority will not restrict itself from giving a positive finding on threat of material injury if there exists other parameters that prove otherwise. Furthermore, the list of threat parameters is not exhaustive and is only indicative.
- xii. Price undercutting and injury margin should be determined for likelihood purposes only considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. Reliance has been placed on *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil. and Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority*.
- xiii. Sufficient evidence has been provided in the petition as regards export orientation, surplus capacity and likelihood.

H.2 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

67. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the likelihood of Dumping and injury to the domestic industry.

H.3 Examination by the Authority

68. The present investigation is a sun set review of anti-dumping duties earlier imposed on imports. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this case, as there are continued dumped imports from China, the Authority is required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product and recurrence of injury to the domestic industry and that whether cessation of duties are likely to lead to recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

69. In the present investigation, as there are continued dumped imports from the subject country, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to recurrence of dumping. Despite the anti-dumping measures in force, the subject country could maintain a significant presence in the Indian market and continued to dump the subject goods. The Authority notes that imports of product under consideration from the subject country has declined by almost 50% compared to base year but remained significant over the current injury period in absolute terms. The analysis of various economic parameters shows overall economic health of the domestic industry has improved during the POI, the Authority notes that this improvement is mainly due to the anti-dumping measures in force. The

Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters as under:

Level of current and past dumping margin

70. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigation and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports from China have continued to be exported at dumped prices. Volume of imports has declined but remains significant even after imposition of anti-dumping duties.

a. Volume of Exports Post POI

71. The authority has undertaken analysis of the volume of exports of subject goods to India from the subject country during post POI (Oct 16-Sept 17) to see whether it reveals any other distinct trend which could be taken into consideration by the Authority. It is observed that imports from China have increased during post POI compared to annualized POI (392 MT). The imports from China were found to be below the normal value of the product. The import prices have shown month wise fluctuation even while generally declining during the post POI period. This indicates likelihood of the imports causing significant undercutting and price depression in the domestic market in the event of cessation of anti-dumping duty. However, this cannot be determined conclusively with limited post POI data.

Post POI import from China (Oct16-Sept17)-DGCI&S

SN	Particulars	Total import (MT) (Oct16-Sep 17)	Dumped import Quantity MT (Oct16- Sep 17)
1	Import volume (Post POI)	568.200	502.20
2	Import value Rs. Lacs (Post POI)	2886.01	2461.84
3	CIF (Import price per KG Post POI)	507.90	490.21
4.	CIF (Import price per KG POI)	613	613

Source DGCI&S

b. Dumping Margin Post POI

72. The authority has undertaken analysis of dumping and injury margin from the subject country during post POI. This analysis has been done on the basis of information submitted by the Domestic Industry and imports data procured by DGCI&S. It is noted that dumping margin is positive and significant during the post POI period. The quantum of dumping was found to follow a rising trend which has almost doubled towards the end of Post POI period. However, it is difficult to arrive at a definite conclusion from the data available for the post POI period.

c. Injury margin POST POI

73. The Authority has also done the Post POI analysis for determination of Injury to the domestic industry, it is found that average injury margin is significant positive and on month wise data analysis a peculiar trend of negative injury in the first four months followed by rising trend of significant injury ranging from 2-36% has been observed. The injury with the Anti -Dumping in existence was found to be positive in later months of post POI period.

d. Price attractiveness of Indian market

74. The price at which the subject goods are being exported by China to India is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. Subject goods being sold by the Domestic Industry are at higher prices than the prices at which product concerned is being exported from China PR to a number of other countries. In this regard, the domestic industry has provided evidence in the form of export price from China to third countries which shows that the dumping margins in respect of exports from China to the third

countries are significant. It is also noted that none of the interested parties have rebutted the submissions of the domestic industry of dumping in the third countries. Further, no contrary evidence has been furnished by any of the interested parties to rebut the claims made by the domestic industry. However, the Authority notes that the total Indian demand has remained around 2000 Metric Ton per annum and it may be insignificant for exporters from subject country.

D. Surplus capacity and Export Orientation of the Chinese Producers

75. While none of the interested parties have responded and provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, imminent increase in capacities and possibility of diversion of present exports to one country to another country, the domestic industry has provided sufficient information of huge capacities with the producers in China and their high export orientation. It is seen that the capacity with individual producers in China is much more than the entire demand in India. The surge of imports on cessation of duty in USA shows that the Chinese Producers have the ability to divert the imports to price attractive destinations. The duties were allowed to cease in 2015 by the US Authority, but it held that there is likelihood of increase in dumped imports, however, material injury to the domestic industry was not foreseeable as the domestic industry in the USA had undergone a change and had limited scope of operations. In the Indian context, given the low level of total Indian demand, aggressive dumping by Chinese exporters may or may not happen.

Name of the company	MT per Annum
M/s Tianjing Chaging Chemcal co	3500
M/s Kaifang Xinghua fine Camical factory	7000
M/s Kaifang Xinghua fine Camical Ltd	15000

Source: website of concerned companies

User Industry's Interest & other issues

76. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the India market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures is not to restrict imports from the subject country in any way, and to affect the availability of the products to the consumers. The Authority notes that with ADD in force, domestic industry's share has grown but imports also continued to hold about 30 % market share. Thus, consumers have maintained two or more sources of supply.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

J.1 Views of the domestic industry

77. The Authority notes that post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. The domestic industry, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:

- a. None of the producers or exporters from China PR has responded in the present sunset review investigation whereas there were various responses in in first SSR conducted.
- b. It appears that the constructed normal value has been determined on the basis of non-injurious price determined for the domestic industry. It is submitted that the actual cost of production needs to be considered and not the notional cost for construction of normal value.
- c. Domestic industry is coming out of the past ill effects of dumping, however remains vulnerable to dumping.
- d. Only in a situation where Designated Authority has come to a conclusion that the injury margin in all situations are negative, the Designated Authority can hold that the Indian market is not attracting to the foreign producers and likelihood of dumping and injury is unlikely.

- e. The imports from China have increased during post POI and the import price has witnessed sharp decline in post POI, with further decline in the most recent period. Consequently domestic industry's selling price has also declined in the most recent period, i.e., September 2017 without corresponding decline in the raw material prices.
- f. Producers and exporters from China PR are exporting the subject goods at dumping prices in other countries' markets at dumped and injurious price.
- g. Huge capacities are available with the producers in the subject country.
- h. USA had also levied anti-dumping duty on the import of Saccharin from China PR for a decade. The antidumping duties ceased in 2015 in USA and immediately imports surged from China to USA.
- i. Duties should be imposed in fixed form and expressed in US\$.

J.2 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested Parties

78. None of the other interested parties have made any submissions with regard to injury and causal link.

J.3 Examination by the Authority

79. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

- a. As regards the argument on determination of normal value, the Authority notes that the standard practice has been followed in this regard and there is no merit in deviating from the methodology followed.
- b. As regards the form of duty, the Authority notes that the form of duty is considered as per the facts and circumstance of the case. In the present case duties are already in force in fixed form expressed in USD.

L CONCLUSIONS

80. After examining the issues raised and the submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, the Authority concludes that:

- i. Though dumping is there but the levels of antidumping margins have decreased in the current period of investigation compared to the previous investigation. Despite the dumping of product under consideration, the injury margin is found to be negative in current period of investigation.
- ii. The imports from subject countries are not being sold below the non- injurious prices of the domestic industry & the price undercutting from subject country during POI is only marginally positive without the ADD in force.
- iii. The performance of the domestic industry has improved in terms of production, capacity utilization, sales, market share, and profits. Return on investment, cash profits, etc. have also shown similar improvement compared to base year.
- iv. Share of imports from China in relation to total imports has further declined over the injury period; imports in relation to production and consumption have also decreased resulting in increase in domestic industry market share and net sales realization translating into mitigation of injury caused by the dumping from subject country.
- v. The Authority has also taken into account other relevant factors, since the ADD is in force since 6th June 2006.
- vi. The post POI analysis was done by taking the constructed normal value and Non-injurious price of the current investigation and kept constant during the month wise analysis. The normal value and Non-injurious price might change during post POI too if other factors are taken into account. Hence, it is difficult to conclusively determine likelihood of dumped imports and consequent injury to the domestic industry based on post POI examination undertaken by the Authority.

- vii. The third country exports and stock inventories of exporters could not be ascertained, as no exporter responded and provided the requisite data. While noting the export orientation of the Chinese producers and price attractiveness of Indian market, it is also felt that domestic industry would be better placed to face off competition as it now has 70% market share.
- viii. Analysis of various economic parameters shows overall economic health of the domestic industry has improved during the POI. The Authority notes that this improvement is mainly due to the anti-dumping measures in force .Thereby the Anti-dumping measures have served the intended purpose of mitigating the unfair advantage usurped/exercised by the exporters by dumping their goods
- ix. The Authority also reiterates that India follows lesser duty rule while arriving at conclusion to impose anti-dumping remedial measures. As there is no injury to the domestic industry during the period of investigation, thereby, the anti-dumping trade remedial measures cannot be extended merely on the basis of dumping only.

M. RECOMMENDATIONS

81. Having observed that the existing antidumping duty is in existence since 6th June 2006, the authority is of the opinion that existing anti-dumping duty has served the intended purpose. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends ceasing of anti-dumping duty on import of subject goods from the subject country recommended vide Notification No. 15/20/2010- DGAD dated 7th December 2011 and enforced vide Customs Notification No. 7/2012-Cus dated 13th January 2012 and as extended by the Central Government vide Notification No. 3/2017-Customs (ADD) dated 19th January, 2017.

M. FURTHER PROCEDURES

82. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority